Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
May 2024 5(5), 1570–1576

ROLE OF GOVERNMENT SCHEMES IN THE SOCIAL AND ECONOMIC UPLIFTMENT OF TRIBAL COMMUNITIES

जनजातीय समुदायों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान में सरकारी योजनाओं की भूमिका

Chandrashekhar Jaiman [1], Santosh Kanwar [2]

[1] Research Director, Associate Professor, Department of Geography, India
[2] Research Scholar, Apex University, Jaipur, India

ABSTRACT

English: India is a vast country. Many cultures are found here. Many castes and tribes live in this country with diverse cultural and social structure. The total population of scheduled tribe community in India is about 8.6%, these communities mainly live in forests, mountains and border areas. Due to this reason, they are very backward in social, educational and economic terms. They are not able to develop fully. These tribes form a special community, whose contribution has not only been in nature conservation, but they have also been the carriers of traditional knowledge, tribal art and culture and values. But reasons like historical exploitation, lack of education and health services, geographical location etc. have brought them to a state of backwardness. Keeping in mind the needs of the tribals, many welfare schemes and programmes are being run by the Central and State Government for their overall development. These are based on education, health, economic development and skill development. The objective of tribal development is to bring them into the mainstream, empower them and protect their traditional rights. Every scheme, whether it is in the field of education or health, will be successful only when the local people are familiar with their need, utility and process. It has been observed in many tribal areas that tribal development schemes are not very successful because their structure is not very simple and clear. Due to this, these schemes are beyond the understanding of the tribal community.

Hindi: भारत एक विषाल देष है। यहाँ अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इस विविध सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना वाले देष में अनेक जातियाँ, जनजातियाँ निवास करती हैं। भारत में अनुसूचित जनजातीय समुदाय की कुल जनसंख्या लगभग 8.6ः है, ये समुदाय मुख्यतः जंगलों, पहाड़ों और सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं। इसी कारण ये सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इनका सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ये जनजातियाँ एक विषिष्ट समुदाय का निमार्ण करती हैं, जिनका योगदान न केवल प्रकृति संरक्षण में रहा है, बल्कि ये पारम्परिक ज्ञान, आदिवासी कला व संस्कृति और मूल्यों की संवाहक भी रही हैं। लेकिन ऐतिहासिक शोषण, षिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, भौगोलिक स्थिति आदि कारणों ने इन्हें पिछड़ेपन की स्थिति में पहुँचा दिया है। जनजातीय आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इनके सम्पूर्ण विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो षिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास एवं कौषल विकास पर आधारित है।
जनजातीय विकास का उद्देष्य इन्हें मुख्यधारा में लाना, सषक्त बनाना तथा इनके परम्परागत अधिकारों की रक्षा करना है। प्रत्येक योजना चाहे वह षिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये तभी सफल होंगी, जब स्थानीय लोग इनकी आवष्यकता, उपयोगिता और प्रक्रिया से परिचित होंगे। कई जनजातीय क्षेत्रों में देखा गया है कि जनजातीय विकास योजनाएँ अधिक सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनकी संरचना अधिक सरल व स्पष्ट नहीं होती है। इस कारण ये योजनाएँ जनजातीय समुदाय की समझ से बाहर होती हैं।

Keywords: Tribes, Economic Backwardness, Scheduled Tribes, Historical Exploitation etc जनजाति, आर्थिक पिछड़ापन, अनुसूचित जनजाति, ऐतिहासिक शोषण आदि

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.5738

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

1. प्रस्तावना

''विविधता में एकता'' भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विषेषता रही है। ये बात यहाँ सार्थक सिद्ध होती है। क्योंकि भारत में अनेक संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं! उनमें से जनजातीय समुदाय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जनजातीयाँ अपनी कला व संस्कृति को हमेषा बनाये रखती हैं। यह प्राकृतिक संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन वर्तमान समय में ये आर्थिक शोषण, षिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी व आर्थिक पिछड़ेपन का षिकार हो रही है।

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक विषाल और विविधतापूर्ण राज्य है। जहाँ जनजातीय समुदायों की एक महत्वपूर्ण आबादी निवास करती है। राज्य में लगभग 13.5ः जनसंख्या जनजातीय समुदायों की है। ये समुदाय मुख्यतः राज्य के दक्षिणी और दक्षिण-पष्चिमी जिलों जैसे- डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में बसे हैं। जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक अलगाव राज्य सरकार के समक्ष एक बड़ी नीति निर्माण की चुनौती प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकार ने इन चुनौतीयों का समाधान करने हेतु कई लक्षित योजनाएँ बनाई है जो केन्द्र सरकार की पहल को राज्य स्तर पर लागू करने के साथ-साथ अपनी क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों का भी संचालन करती है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देष्य अनुसूचित जनजातीयों की सामाजिक सुरक्षा, षिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सषक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को सुनिष्चित करना है।

2. उद्देष्य

1. आदिवासी जनजातीय समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान का अध्ययन करना।
2. राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त रोजगार, स्वरोजगार और कौषल विकास के अवसरों की पहचान करना।
3. आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में लागू की जा रही प्रमुख सरकारी योजनाओं का अवलोकन करना।
4. जनजातीय योजनाओं की जनजातियों तक पहुुँच, क्रियान्वयन और परिणामों का मूल्याँकन करना।
5. योजनाओं के क्रियान्वयन के समय आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।

शोध क्षेत्र: प्रस्तुत अध्ययन के लिए दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों (डूंगरपुर व उदयपुर) को शोध हेतु चुना गया है, क्योंकि यह क्षेत्र जनजातीय आबादी का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ भील, डामोर व कथौड़ी जनजाति निवास करती है।

अनसंधान पद्धति: शोध हेतु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही आँकड़ो का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय परिवारों से साक्षात्कार, फोकस ग्रुप डिस्कषन, पंचायत सदस्य व स्थानीय अधिकारियों से बातचीत के माध्यम से प्राप्त किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन सरकारी रिर्पोट, दस्तावेज, सेंसस आदि के द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन मिश्रित पद्धति पर आधारित है। इसमें जनजातीय योजनाओं प्रभाव जनजाति की आर्थिक स्थिति व सामाजिक स्थिति पर कितना रहा इसकी जाँच मात्रात्मक व गुणात्मक तरीकों से की गई है।

3. प्रमुख योजनाएँ

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ

राज्य सरकार द्वारा संचालित जनजातीय योजनाओं को जानने से पूर्व केन्द्र स्तर पर संचालित योजनाओं को जानना अतिआवष्यक है। भारत सरकार का जनजातीय विकास मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सषक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित करता है। इन योजनाओं का उद्देष्य जनजातीय आबादी को मुख्यधारा से जोड़ना उसकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना और उन्हें स्थायी आजीविका एवं स्तर प्रदान करना है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित है-

1) जनजातीय अनुसंधान संस्थान (ज्त्प्): इसका प्रमुख उद्देष्य अनुसूचित जनजातियों की परंपराओं, संस्कृति, बोली, सामाजिक व्यवस्था और आवष्यकताओं का गहन अध्ययन करना है ताकि योजनाओं को नवाचार और संवेदनषीलता के साथ लागू किया जा सके। वर्तमान में देषभर में 26 से अधिक ज्त्प् संस्थान कार्यरत हैं। जिनका प्रमुख उद्देष्य जनजातीय सर्वेक्षण करना जनजातियों से सम्बन्धित डेटा संकलन व विष्लेषण करना एवं जनजातीय मामलों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
2) वन बंधु कल्याण योजना: इसे प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना भी कहा जाता है। यह योजना 2014 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, जिसका उद्देष्य जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिष्चित करना है। यह योजना केवल षिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दस प्रमुख क्षेत्रों जैसे- बुनियादी ढाँचा, षिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, कौषल विकास, कृषि, वित्तीय

समावेषन, सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति संरक्षण को समेटती है। हालाँकि यह योजना विभिन्न राज्यों में समान रूप से प्रभावी नहीं है। कई जिलों में यह योजना सिर्फ प्रषासनिक फाइलों में सिमट गई। तथा कुछ राज्यों में अत्यधिक सफल रही।

3) प्रधानमंत्री वन धन योजना:यह योजना जनजातीय आबादी को लघु वन उपज आधारित आजीविका देने हेतु शुरू की गई थी। इसका उद्देष्य वन उत्पाद संग्रहण करने वाले कथौड़ी समुदाय को संगठित कर उन्हें प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन से जोड़ा जाए।
4) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (म्डत्े): जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्रदान करने के उद्देष्य से म्डत्े की स्थापना की गई। उन विद्यालयों में छात्रावास, भोजन, गणवेष और पुस्तकों सहित षिक्षा मुफ्त दी जाती है। इसका प्रभाव यह रहा कि जहाँ विद्यालय स्थापित हुए। वहाँ बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार देखा गया। साथ ही बालिका षिक्षा में भी वृद्धि हुई।
5) पोषण अभियान और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: केन्द्र सरकार ने विषेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण को कम करने हेतु पोषण अभियान चलाया है। जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों की मदद से निरन्तर निगरानी, आयरन और कैल्षियम सप्लीमेंटेषन और बालिका पोषण षिक्षा दी जाती है। साथ ही डिजिटल भारत अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, मोबाईल एप प्रषिक्षण और डिजिटल भूगतान पर प्रषिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं।
6) ट्राइफेड ;ज्त्प्थ्म्क्द्ध: यह एक सहकारी विपणन संघ है जो जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम करता है।
7) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ;च्डैद्ध: यह योजना कक्षा 11 से ऊपर की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
8) राष्ट्रीय विदेषी छात्रवृत्ति योजना: यह योजना विदेष में उच्च षिक्षा करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य करती है। ताकि वे शैक्षिक पिछड़ेपन की अवस्था से बाहर निकल सकें। व स्वयं का विकास कर सकें।

भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन योजनाओं का उद्देष्य जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को सषक्त बनाना है। सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएँ जनजातीय लोगों को षिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इन योजनाओं का प्रभाव केवल जनजातीय समुदायों तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि यह समग्र भारतीय सामाजिक विकास में भी अहम् भूमिका निभाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ

राज्य सरकार द्वारा जनजातीय विकास हेतु समय-समय पर अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हंै। जो इस प्रकार है-

1) षिक्षा से सम्बन्धित योजना: षिक्षा की दृष्टि से राज्य में शारदा बालिका छात्रवृत्ति योजना, आदिवासी बालिका छात्रावास योजना चलाई जा रही है। शारदा बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत् कक्षा 6 -12 वर्ष की जनजातीय छात्राओं को प्रतिवर्ष 3000-5000 रूपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। जिससे बालिकाओं को स्कूल छोड़ने से रोका जा सके। साथ ही आदिवासी बालिका छात्रावास योजना के तहत् बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें भोजन, किताबें व षिक्षक सहायता शामिल है।

प्रभाव: इन योजनाओं के माध्यम से जनजातीय छात्रों को षिक्षा के बुनियादी अवसर प्राप्त हुए हैं। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है। विद्यालयों की उपलब्धता भी बढ़ी है तथा बालिका षिक्षा में सुधार हुआ है।

2) जनजातीय उपयोजना (ज्ैच्): राजस्थान सरकार की जनजातीय विकास रणनीति का आधार जनजातीय उप योजना है। जो राज्य बजट का वह हिस्सा होती है जो केवल अनुसूचित जनजातियों की भलाई और विकास पर खर्च किया जाता है। यह योजना 20ःसे अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में लागू होती है। इस योजना का मुख्य उद्देष्य न केवल सामाजिक कल्याण योजनाओं तक सीमित है, बल्कि यह कृषि, षिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी सुविधा और रोजगार के क्षेत्रों में भी योजनाओं का समावेष करती है। यह विभागीय बजट के अन्दर ही जनजातीय आबादी के अनुपात के अनुसार धन का प्रावधान करती है जिससे समन्वित विकास को बढ़ावा मिलता है।

प्रभाव: ज्ैच् के तहत जनजातीय समुदायों को षिक्षा, स्वास्थ्य, जल, आवास और रोजगार जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती है। जिससे उनमें जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। यह जनजातीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं। जिससे सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और समाज में समान अवसर मिलते हैं।

3) स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजना: जनजातीय क्षेत्रों में जननी षिषु सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी एवं आषा कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से पोषण, मातृ-षिषु स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा को सषक्त करना शामिल है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राषि प्रदान की जाती हे। जिससे प्रसव सम्बन्धित मृत्युदर में कमी लाने का प्रयास किया जाता है। राज्य में 104 व 108 एंबुलेंस सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाती है। ताकि माताओं को दूरस्थ क्षेत्रों से अस्पताल लाया जा सके , लेकिन

अभी अनेक गाँवों मंे स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की दूरी, डाॅक्टरों की अनुपलब्धता , दवाओं की अनियमित आपूर्ति और महिला स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जैसे- मुद्दे मौजूद हैं। जिससे योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता।

4) जनजातियों के लिए विषेष रोजगार सृजन योजनाएँ: सरकार ने जनजातियों के लिए रोजगार सृजन योजनाएँ लागू की है, इनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्टैंड-अप-इंडिया योजना। इन योजनाओंके माध्यम से व्यापार और उद्योग की शुरूआत के लिए ऋण, सरकारी सहायता और कौषल प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रषिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कारीगरी, सिलाई, बुनाई और अन्य श्रमिक कौषलों में प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है। जिससे जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। ताकि उनसे आय स्रोत् बढ़ सकें तथा जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातीयों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

5) जनजातीय आजीविका योजनाएँ और स्वरोजगार प्रोत्साहन: राजस्थान सरकार ने जनजातीय समुदायों के लिए स्वरोजगार प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे जनजातीय स्वरोजगार योजना, राजीव गाँधी ग्रामीण आजीविका मिषन और वनोपज विपणन समर्थन योजना शुरू की है। राजीव गाँधी ग्रामीण आजीविका मिषन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें प्रषिक्षण, बीज पूंजी और विपणन सहायता दी जाती है। इन समूहों द्वारा हस्तषिल्प, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में ये समूह आत्म-निर्भरता की दिषा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उन उपज योजनाओं के तहत् तेंदूपत्ता, महुआ, शहद आदि की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाती है। जिससे जनजातियों को मुनाफा मिल सके। हालांकि बाजार संपर्क की कमी, विपणन दक्षता की अनुपस्थिति और मूल्य निर्धारण की अपारदर्षिता इन प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर रही है।

6) जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियाँ: राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने हेतु तथा जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन के लिए आकर्षक बनाने के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं इन योजनाओं के तहत् जनजातीय इलाकों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है जिससे इन इलाकों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय अपनी पारंपरिक कला और षिल्पकला का प्रदर्षन करते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा कृषि और हस्तषिल्प उत्पादों को बाजार में ले जाने के लिए जनजातीय समुदायों को प्रषिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को न केवल वित्तीय सहायता मिलती है, बल्कि उन्हें उनके पारंपरिक पेषों के साथ-साथ नए व्यवसायों की शुरूआत करने के अवसर भी मिलते हैं। जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है, और वे समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम होते हैं तथा अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित भी रख पाते हैं।

7) प्रषासनिक ढ़ाँचा और ज्।क् की भूमिका: राजस्थान सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ज्तपइंस ।तमंक्मअमसवचउमदज ;ज्।क्द्धप्राधिकरण की स्थापना की है। जो योजनाओं के अनुमोदन, निगरानी और संसाधन आंवटन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद्, पंचायत राज प्रतिनिधित्व और ग्राम विकास समितियां कार्य करती हैं। इन संस्थाओं का कार्य-योजना निर्माण में जनजातीय भागीदारी को सुनिष्चित करना है हालाँकि, अक्सर यह देखा गया है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में नौकरषाही हावी रहती है, जिससे समुदाय की आवाज योजनाओं में शामिल नहीं हो पाती है। आवष्यकता है कि इन संस्थाओं को अधिक पारदर्षी, विकेन्द्रीकृत और उत्तरदायी बनाया जाए।

8) उच्च षिक्षा और अनुसंधान: राजीव गाँधी जनजातीय विष्वविद्यालय की भूमिका

जनजातीय क्षेत्रों डूंगरपुर, बांसवाड़ा में स्थापित राजीव गाँधी जनजातीय विष्वविद्यालय जिसे वर्तमान में गोविन्द गुरू जनजातीय विष्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसे 2012 में स्थापित किया गया था तथा इसका नाम बदलकर 2016 में गोविन्द गुरू जनजातीय विष्वविद्यालय कर दिया गया। यह विष्वविद्यालय बांसवाड़ा, डूंगरपुर में स्थापित सभी काॅलेजों पर अधिकार क्षेत्र रखता है। यह विष्वविद्यालय न केवल उच्च षिक्षा का केन्द्र है बल्कि जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक अध्ययन, साहित्यिक विकास और प्रषासनिक सेवाओं की तैयारी में भी सहायक है। यहाँ पर जनजातीय इतिहास, लोक कला, समाजषास्त्र व जनजातीय नीति जैसे विषयों पर केन्द्रित पाठ्यक्रम चलाए जाते है। यह विष्वविद्यालय जनजातीय छात्रों को जीवन में सहभागिता, शोधकार्य और प्रतिस्पर्धा सोच के मंच प्रदान करता है। इस विष्वविद्यालय की स्थापना जनजातीय समुदायों की षिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देष्य जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च षिक्षा प्रदान करना और उन्हें समाज में मुख्यधारा से जोड़ना है।

इस विष्वविद्यालय की भूमिका इन समुदायों के लिए एक सषक्तीकरण के रूप में कार्य करती हैं। जो लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से हाषिये पर थे। यहाँ पर छात्रों को उनके पारम्परिक ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक षिक्षा का समावेष किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप ये छात्र न केवल उच्च षिक्षा प्राप्त करते है। बल्कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

योजनाओं की तुलना, प्रभाव एवं विष्लेषण:-

शोध मे 400 उत्तरदाताओं द्वारा जनजातीय योजनाओं से सम्बन्धित कुछ प्रष्न पूछे गये तथा उनसे उनका स्तर ज्ञात किया गया। जो इस प्रकार है।

सारणी-1 क्या आप राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी जनजातीय योजना के लाभार्थी हुए हैं?

विकल्प	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
हाँ	232	58
नहीं	168	42

विश्लेषण: लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं ने बताया कि वे किसी न किसी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। इनमें लगभग 58ः उत्तरदाता योजनाओं से लाभान्वित हुए। जबकि 42ः उत्तरदाता जनजातीय योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

सारणी 2 आपने निम्न में से किस योजना का लाभ लिया है?

योजना का नाम	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
शारदा बालिका छात्रवृत्ति योजना	62	15.5
जननीसुरक्षा योजना	174	43.5
स्वरोजगार योजना	112	28
वन उपज समर्थन योजना	82	20.5
छात्रावास सुविधा	70	17.5

विश्लेषण: सारणी 2 से स्पष्ट है कि जननी सुरक्षा योजना अधिक उपयोगी है, जबकि षिक्षा व आर्थिक योजनाओं की पहुँच अपेक्षाकृत कम रही। जननी सुरक्षा योजना का लाभ 43.5ः लोगों ने उठाया।

सारणी 3 आपको योजना की जानकारी कहाँ से मिली?

सूचना स्रोत्	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
पंचायत/ग्रामसभा	152	38
आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	112	28
स्कूल/षिक्षक	72	18
मीडिया/टीवी/रेडियो	42	10.5
अन्य	22	5.5

विश्लेषण: सारणी 3 से स्पष्ट है कि पंचायत और आषा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय को अधिक जनकारी प्राप्त हुई है। जिससे उसकी भूमिका स्पष्ट होती है।

सारणी 4 क्या सरकारी योजनाओं के तहत् मिलने वाली सेवाएँ संतोषजनक हैं?

विकल्प	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
पूरी तरह संतोषजनक	64	16
आंशिक रूप से	204	51
असंतोषजनक	132	33

विश्लेषण: सारणी 4 लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा लोगों को सेवाओं की गुणवत्ता या पहुँच मंे कमी महसूस हुई है। लगभग 33ः उत्तरदाताओं ने कहा कि वह योजनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। जबकि 16ः उत्तरदाताओं ने कहा कि वह योजनाओं से पूर्णतः संतुष्ट हैं।

सारणी 5 आपकी राय में राज्य की कौनसी योजना सबसे अधिक प्रभावी रही?

योजना का नाम	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
जननी सुरक्षा योजना	134	33.5
छात्रवृत्ति/छात्रावास योजना	116	29
आजीविका एवं स्वरोजगार योजना	102	25.5
वन उपज विपणन योजना	28	7
कोई भी नहीं	20	5

विश्लेषण: सारणी 5 मातृ-षिषु स्वास्थ्य योजना अर्थात् जननी सुरक्षा योजना सबसे अधिक प्रभावी मानी गई। छात्रावास योजना भी प्रभावी रही। जबकि आजीविका योजनाओं को भी पर्याप्त प्रतिक्रिया मिली। लगभग 33.5ः लोगों ने कहा कि वह जननी सुरक्षा योजना से संतुष्ट हैं तथा सबसे अधिक उपयोग भी इसी योजना का किया गया है।

भारत में जनजातीय समुदायों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूर्णरूपेण मूल्यांकन तब तक अधुरा है जब तक उनकी आपसी तुलना, व्यावहारिक प्रभाव और लाभार्थियों के अनुभव को समग्र रूप से न परखा जाए।

केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही स्तरों पर अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है। जिनका उद्देष्य जनजातीय आबादी को समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सषक्तिकरण और सांस्कृतिक पहचान प्रदान करना है, परन्तु योजनाओं के उद्देष्य एक जैसे होते हुए भी उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया, पहँुच और प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है।

जब हम सरकारी योजनाओं के प्रभाव की बात करते हैं तो स्पष्ट होता है कि राज्य योजनाओं की स्थानीय समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक बसावट, भाषाई विविधता और भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया होता है। राज्य योजनाएं जमीन से अधिक जुड़ी होती है। हालाँकि, राज्य योजनाओं की जमीनी पहुँच अच्छी होती है। लेकिन उनकी वित्तीय क्षमता और तकनीकी विस्तार सीमित होता है।

राज्य सरकार की योजनाएँ अक्सर धन की कमी या पारदर्षिता की कमी से जूझती है। इसी प्रकार वन उपज मूल्य समर्थन योजना केन्द्र से प्राप्त फंडिंग के तहत् तो प्रभावी है, लेकिन बाजार मूल्य निर्धारण और भंडारण और विक्रय की संरचना अब भी राज्य स्तर पर कमजोर है।

योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित चुनौतियाँ

1) परिवहन सुविधाओं की कमी।
2) सड़कों की खराब स्थिति।
3) षिक्षा की कमी।
4) स्वास्थ्य केन्द्रों व विद्यालयों का दूर-दराज क्षेत्रों में स्थापित होना।
5) शिक्षकों की कमी, स्वास्थय कर्मचारियों की संख्या में कमी।
6) जनजातीयों में तकनीकी ज्ञान की कमी।
7) सरकार का योजनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की कमी।
8) भौगोलिक अलगाव पहाड़ी क्षेत्रों में बसे होने के कारण योजनाओं की पहुँच सीमित होती है।
9) भ्रष्टाचार और बिचैलियों की भूमिका।
10) प्रशासनिक अक्षमता एवं योजना क्रियान्वयन की धीमी गति।

5. निष्कर्ष

अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों की योजनाओं की अपनी-अपनी उपयोगिता है। जहाँ केन्द्र सरकार की योजनाएँ नीति, दिषा और वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं राज्य सरकार की योजनाएँ भौगोलिक संरचना, स्थानीय आवष्यकताओं, भाषा-संस्कृति की समझ और सीधे सम्पर्क के कारण अधिक प्रभावी साबित होती है। जनजातीय विकास की दिषा में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा, जब दोनों स्तरों की सरकारें परस्पर सहयोग करते हुए योजनाओं को समन्वित दृष्टिकोण से लागू करें। जिससे प्रभावषीलता, पारदर्षिता और सहभागिता सुनिष्चित हो सके। केवल बजट और कागजी प्रगति नहीं, बल्कि योजनाओं के व्यावहारिक प्रभाव, आर्थिक लाभ, लाभार्थी संतुष्टि और

दीर्घकालिक परिणाम ही किसी योजना की सफलता का मापदंड होना चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जनजातीय योजनाओं का प्रभाव षिक्षा, आर्थिक विकास व सामाजिक विकास पर पड़ा है। इससे कुछ हद तक जनजातीय सुधार हुआ है। लेकिन अभी सम्पूर्ण विकास बाकी है।

सन्दर्भ

सिंह, आर (2018) वन धन योजना के माध्यम से जनजातीय आर्थिक विकास। जनजातीय आर्थिक विकास समीक्षा 2(1). पृ.सं. 33-45।

दास, ए. और जोषी, एन. (2016) राजस्थान विकास समीक्षा। 8(3). पृ.सं. 102-115।

गुप्ता, आर. (2017) जनजातीय महिलाओं को सषक्त बनाने में कौषल विकास योजनाओं की भूमिका। महिला और विकास पत्रिका, 12(4). पृ.सं. 134-146।

दत्ता, एस. और राॅय, एस. (2017) भारत में जनजातीय विकास में सामाजिक-आर्थिक अवरोधों का विष्लेषण। भारतीय आर्थिक समीक्षा 4(5). पृ.सं. 56-69।

शर्मा, पी. और जोषी, पी. (2020) जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक और शैक्षिक सुधार। जनजातीय संस्कृति और षिक्षा प्रक्रिया 22(5). पृ.सं. 145-158।

राॅय, पी. (2019) राजस्थान में जनजातीय षिक्षा नीतियाँः एक लम्बी अवधि का अध्ययन। भारतीय षिक्षा पत्रिका।

शर्मा, आर. (2017) भारत में जनजातीय स्वास्थ्य पहलों का प्रभाव। स्वास्थ्य नीति समीक्षा, 16 (2). पृ.सं. 45-58।